



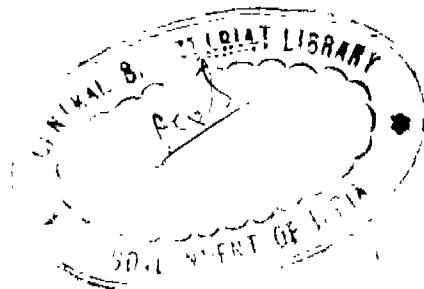
भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. ६९७]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर १९, १९९९/कार्तिक २८, १९२१

No. 697]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 19, 1999/KARTIKA 28, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, १९ नवम्बर, १९९९

आयकर

का. आ. ११५०(अ).—आयकर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) की धारा २९५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा आयकर नियमावली, १९६२ में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

१. (१) इन नियमों को आयकर (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, १९९९ कहा जाएगा।

(२) ये नियम महली अप्रैल, १९९७ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

२. आयकर नियमावली, १९६२ में, नियम ६षष में, "दस हजार" शब्दों, जहाँ कहीं भी वे घटित हों, के स्थान पर "बीस हजार" शब्दों को रखा जाएगा।

[अधिसूचना सं. १११३४/फा. सं. १४२/४५/९९-टीपीएल]

एस. बाला सुब्रमनियन, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम दिनांक २६-३-१९६२ की अधिसूचना का.आ. ९६२(अ) के तहत प्रकाशित किये गये थे और दिनांक ६-१०-९९ की अधिसूचना द्वारा का.आ. १०१२(आ.) के अन्तर्गत इनमें अन्तिम बार संशोधन किया गया था।

व्याख्यात्मक ज्ञापन :—आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ४०क(३) का संशोधन वित्त (सं-२) अधिनियम, १९९६ द्वारा किया गया था जिसके द्वारा किसी बैंक पर आहरित रेखांकित चैक अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ़्ट के अलावा अन्यथा द्वारा किये गये किसी व्यय के भुगतान की ऊपरि सीमा को बीस हजार रुपये तक बढ़ाया गया था। रेखांकित चैक अथवा बैंक ड्राफ़्ट के अलावा अन्यथा द्वारा किये गये किसी व्यय जो २० हजार रु. से अधिक है, को बीस प्रतिशत की कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6घष में उन मामलों एवं परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है जिनमें धारा 40क(3) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक रकम में भुगतान किसी बैंक पर आहरित रेखांकित बैंक अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त किया जा सकता है। तथापि, उक्त नियम में 20 हजार रु. की सीमा को शामिल नहीं किया गया है। नियमानुसार दस हजार रु. की यह सीमा जारी रहेगी।

अतः, 1 अप्रैल, 1997 को नियम 6घष को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि इस विषमता को दूर किया जा सके।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियम 6घष के प्रस्तावित संशोधन में भूतलक्षी प्रभाव से किसी कर निर्धारिती के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 1999

INCOME-TAX

S.O. 1150(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Thirty-first Amendment) Rules, 1999.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1997.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 6DD, for the words “ten thousand”, wherever they occur, the words “twenty thousand” shall be substituted.

[Notification No. 11134/F.No. 142/45/99-TPL]

S. BALASUBRAMANIAN, Under Secy.

Foot Note.—The Principal rules were published vide Notification vide S.O. No. 969(E) dated 26-3-1962 and last amended by notification published under S.O. No. 1012 dated 06-10-1999.

Explanatory Memorandum.—Section 40A(3) of the Income-tax Act, 1961 was amended by the Finance (No. 2) Act, 1996 enhancing the upper limit for payment of any expenditure incurred otherwise than by a crossed cheque drawn on a bank or by a crossed bank draft to rupees twenty thousand. Twenty per cent of any expenditure, exceeding rupees twenty thousand, made otherwise than by a crossed cheque or a draft is not to be allowed as deduction.

Rule 6DD of the Income-tax Rules, 1962 prescribes the cases and circumstances in which payments in a sum exceeding the limit fixed under section 40A(3), may be made otherwise than by a crossed cheque drawn on a bank or a crossed bank draft. However, the limit of rupees twenty thousand has not been incorporated in the said rule. The limit, as per the rule continued to be rupees ten thousand.

It is therefore proposed to amend rule 6DD with effect from the 1st day of April, 1997 so as to remove this anomaly.

It is certified that the retrospective effect to the proposed amendment to the said rule 6DD shall not prejudicially affect the interest of any assessee.